उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून

E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 14 अगस्त, 2019(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–06(08/61)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में हरेला समापन समारोह के अवसर पर कृषि, बागवानी के क्षेत्र में योगदान के लिये थलीसैंण निवासी श्री अनूप पटवाल को **जसोदा नवानी हरेला सम्मान** के रूप में 51 हजार की धनराशि प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने धाद महिला एकांश, हरेला साथियों के साथ ही स्कूली छात्रों को भी सम्मानित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हमारा देश संस्कृति की विविधताओं तथा जैव विविधता का खजाना है। हमारे प्रदेश की भी इसमें बड़ी हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्थायें समाज को जीवन्त बनाने के साथ ही परम्पराओं को संजोने का कार्य कर रही है। आज जब कि हर घंटे में एक बोली तथा हर दिन एक भाषा समाप्त हो रही है। इन्हें बचाने के लिये सरकारी स्तर पर तो प्रयास हो ही रहे हैं किन्तु इस दिशा में संस्थायें भी बेहतर कार्य कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि हरेला पर्व अतरंगता से जुड़ा है, हमारी लोक परम्पराएं हमें जीवन्त बनाती हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवी संस्थाओं से स्वेच्छिक चकबन्दी की ओर ध्यान देने की भी अपेक्षा की। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत खेती को बढ़ावा देने के साथ खेती के बदलते स्वरूप पर भी ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों पर खेत तैयार कर उन्हें अपने जीवन यापन का साधन बनाया अब बंजर हो रहे ऐसे खेतों को उपजाऊ बनाने के लिये हमें आगे आना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 1.80 करोड़ पेड लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के तहत गत वर्ष ऋषिपर्णा व कोशी को पुर्नजीवित करने के लिये इनके उद्गम स्थलों पर व्यापक जन सहयोग में एक ही दिन में लाखों वृक्षों का रोपण किया गया। लगाये गये पेड जीवित रहें इसके भी प्रयास किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने श्री पटवाल द्वारा कृषि बागवानी की उत्पादकता के लिये किये जा रहे प्रयास व प्रयोग की सराहना करते हुए कहा कि इससे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी तथा वे कृषि की अधिक आय वाली सम्भावनाओं की ओर आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे उत्पादों पर ध्यान दिया जाय जिन्हें जंगली जानवरों से कम नुकसान होता हो।

उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने तथा खेती के प्रति ध्यान देने के लिये राज्य सरकार द्वारा अनेक सहूलियतें दी जा रही है। प्राकृतिक खेती व खेती के तरीकों में बदलाव लाने में भी उन्होंने संस्थाओं से सहयोग की अपेक्षा की। सेब, अखरोट, कीवी के साथ ही उन्होंने इंडस्ट्रियल हेम्प की खेती के प्रति भी ध्यान देने पर बल दिया। यह भी ग्रामीण आर्थिकी के मजबूत आधार बन सकते हैं।

इस अवसर पर विधायक श्री राजेश शुक्ला, धाद संस्था के अध्यक्ष श्री लोकेश नवानी, सचिव तन्मय ममगाई, पद्मश्री बसन्ती बिस्ट सहित बड़ी संख्या में धाद से जुड़े लोग उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 14 अगस्त, 2019(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–05(08/60)

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि महिलाओं और बच्चों का सम्पूर्ण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण, कुपोषित बच्चों के कुपोषण से मुक्ति हेतु किये जा रहे कार्य एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को मिशन मोड में सम्पन्न किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग के अन्तर्गत संचालित केन्द्रपोषित योजनाओं में से आई0सी0डी0एस0 सर्विसेज के अन्तर्गत वेतन तथ मानदेय के प्रतिमाह भुगतान की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 5000 आंगनवाड़ी केन्द्र तैयार किये जाने हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण को प्राथमिकता में लेते हुए वर्षवार प्लान तैयार कर योजना को पूर्ण किया जाए। भवनों को भूकम्परोधी तथा आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत निर्मित किए जाएं। आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु बाम्बू हाउस के विकल्प का भी अध्ययन कर लिया जाय।

मुख्य सचिव ने कहा कि कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों की लगातार ट्रेकिंग की जाए। प्रदेश के ऐसे जनपदों का चयन किया जाय, जिनमें सबसे अधिक बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। इन जनपदों में कुपोषण मुक्ति के लिए किये गये प्रयासों का अध्ययन व विश्लेषण कर अन्य जिलों के लिए भी योजना बनाई जाय। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों द्वारा कुपोषण से मुक्ति के लिए की गयी सराहनीय पहलों का अध्ययन कर प्रदेश हेतु योजनाएं तैयार की जाएं। जिन राज्यों में एनिमिया से ग्रसित महिलाओं में कमी आयी है, उन राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन कर प्रदेश के लिए भी एक पॉलिसी तैयार की जा सकती है।

सचिव श्री अमित नेगी ने महिला एवं बाल विकास विभाग को कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु गृह स्थापित करने एवं बच्चों की पूर्ण सुरक्षा हेतु व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष कम उपस्थिति के कारणों का अध्ययन कर बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के प्रयास किये जाएं।

इस अवसर पर निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री झरना कमठान एवं उप निदेशक श्रीमती सुजाता भी उपस्थित थीं।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 14 अगस्त, 2019(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–04(08/59)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी है। उन्होंने रक्षाबंधन को विशेष रूप से भाई–बहन के आपसी प्रेम व सहयोग का पर्व बताते हुए कहा कि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाईयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके सुख, समृद्धि व दीर्घायु की कामना करती हैं। रक्षा बन्धन का पर्व महिलाओं के सम्मान से जुड़ा पर्व भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी समृद्ध, सांस्कृतिक परम्पराओं से जुड़े इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व भी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति हमारा प्रयास निरन्तर जारी है। महिलाओं को सशक्त किए बिना हम एक समृद्ध उत्तराखण्ड की कल्पना पूरी नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुविधा के लिये रक्षाबंधन के अवसर पर उन्हें उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा करने की भी सुविधा प्रदान की गई है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 14 अगस्त, 2019(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–03(08/58)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में आयोजित रक्षाबन्धन समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने मुख्यमंत्री की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार भावनाओं व पवित्रता का त्योहार है। उन्होंने कहा कि यह संयोग है कि इस वर्ष रक्षा बन्धन का पावन पर्व व भारत का स्वतंत्रता दिवस एक ही दिन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण से ही देश मजबूत हो सकता है। इस दिशा में अनेक प्रयास हुए हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

इस अवसर पर विधायक श्री गणेश जोशी, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्री विनय गोयल, मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी श्री धीरेन्द्र पंवार, श्रीमती बृजेश गुप्ता, साधवी प्राची व बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी।

इससे पूर्व प्रजापिता ईश्वरी विश्व विद्यालय ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ राजयोगिनी बी.के ऊषा दीदी ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। उन्होंने कहा कि आगामी 06 अक्टूबर को देहरादून में व्यसन से मुक्ति के लिए प्रजापिता ईश्वरी विश्व विद्यालय ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया है।

इस अवसर पर प्रजापिता ईश्वरी विश्व विद्यालय ब्रह्मा कुमारीज से बी.के नीलम, बी.के सोनिया, श्री सुशील कुमार, श्री रमेश कपूर, श्री राजकुमार जोशी, श्री गौरव कपूर आदि उपस्थित थे।

इसके पश्चात मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भानियावाला स्थित वैडिंग प्वाइंट में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं ने मुख्यमंत्री की कलाई में राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब महिलाएं सामाजिक व आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, तब ही देश तेजी से उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। आज हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है। केन्द्र व राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पिछले दो सालों में उत्तराखण्ड में प्रति हजार बालकों पर बेटियों की संख्या 908 से बढ़कर 938 हो गई है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में राज्य सरकार अनेक प्रयास कर रही है। राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज के 05 लाख रूपये तक का ऋण दे रही है। महिला उद्यमियों के लिए बिना ब्याज के व्यक्तिगत रूप से एक लाख रूपये तक का लोन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत धात्री महिलाओं को 06 हजार रूपये का पोषण भत्ता दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की संसद ने तीन तलाक बिल को पास कर हमारी मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाया है। सामाजिक विषमता को समाप्त कर उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर के लोगों को समाज व देश की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के 70 साल बाद वास्तव में अब देश एक हुआ है। अब कश्मीर के लाल चौक पर भारतीय झण्डा फहराया जायेगा। अब देश में एक निशान एक विधान लागू होगा।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

सम्मिलित प्रयासों से मिली बीसीसीआई से मान्यता : मुख्यमंत्री

- **क्रिकेट जगत में उत्तराखण्ड को मिलेगी नई पहचान।**
- **पूर्व मंत्री श्री हीरा सिंह बिष्ट एवं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड (CAU) के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का आभार जताया, मुख्यमंत्री ने भी दी बधाई।**

उत्तराखण्ड को बीसीसीआई से मान्यता मिलने पर बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में पूर्व मंत्री श्री हीरा सिंह बिष्ट एवं **क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड (CAU)** के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी श्री बिष्ट व एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड को बीसीसीआई की मान्यता मिलने से राज्य के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्रिकेट की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के अवसर प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित सर्वोपरि होता है। खेल भावना यही कहती है कि सफलता के लिए टीम भावना से काम किया जाए। उत्तराखण्ड को बी.सी.सी.आई. से मान्यता दिलाने के लिए तमाम राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को परे रखकर सभी ने मिलकर कोशिश की। इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। आगे भी हमें इसी भावना को बनाए रखना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खिलाड़ी और खेल प्रेमी लम्बे समय से इसका इन्तजार कर रहे थे। इससे राज्य में क्रिकेट को नया मुकाम मिलेगा। अब हमारे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे क्रिकेट जगत में उत्तराखण्ड को नई पहचान भी मिलेगी।

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड (CAU) को बीसीसीआई से मान्यता मिलने पर मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के लिए विशेष उपलब्धि बताते हुए कहा कि पिछले 19 वर्षों से किये जा रहे प्रयासों को अब सफलता मिली है। अब राज्य में राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट की बड़ी प्रतिस्पर्धाएं होंगी। जिससे राज्य में पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य की इस उपलबिध के लिए सभी पदाधिकारियों को भी बधाई दी।

इस अवसर पर श्री पी.सी. वर्मा, श्री महिम वर्मा, श्री संजय गुंसाई, श्री अवनीश वर्मा, श्री धीरज खरे, श्री रोहित चौहान, श्री संजय रावत, श्री शिवपाल सिंह, श्री इन्द्रमोहन भाटिया, श्री मनोज अरोड़ा आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 14 अगस्त, 2019(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–03(08/58)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सुभाष रोड़ स्थित गुरूनानक निवास में गुरूनानक देव के 550 प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में ननकाना साहिब से प्रारम्भ हुई यात्रा का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने गुरूनानक जी को भारतीयता की पहचान दिलाने वाला महान संत बताते हुए कहा कि आधुनिक भारत के मध्य काल में मुगलों के शासन काल में अपने समाज व संस्कृति की रक्षा के लिये दिये गये उनके योगदान को हमारा समाज सदैव याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के पराधीनता के दौरान की विपरीत परिस्थितियों में देश को मार्गदर्शन देने का जो महान कार्य उन्होंने किया वह सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूनानक देव जी ने हमें सीख दी है कि ईश्वर को प्राप्त करने का प्रमुख साधन आपसी प्रेम ही है। हम उनके विचारों को आत्मसात कर ही बेहतर समाज का निर्माण करने में सफल हो सकेंगे।

इस अवसर पर विधायक श्री खजान दास, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, भाजपा नेता श्री अनिल गोयल, श्री बलजीत सोनी आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास से बन रहा नया भारतः मुख्यमंत्री

- **धारा 370 के प्रभावहीन होने से जम्मू कश्मीर में लिखी जाएगी विकास की नई इबारत।**
- **जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, कार्य–संस्कृति में सुधार और युवाओं को रोजगार सर्वोच्च प्राथमिकता।**
- **स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को बधाई दी।**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 72 वीं वर्षगांठ पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों, देश रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सेना के जवानों व उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास से हमें नए भारत का निर्माण करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखण्ड को सैन्यधाम की संज्ञा दी है। हमारी सरकार शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है। देश के बहुत से राज्य बाढ़ की दुश्वारियों से जूझ रहे हैं, हम उनके कष्ट व पीड़ा को समझ सकते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। प्रदेश में भी आपदा से जन–धन की हानि हुई है। प्रभावितों को हर सम्भव मदद पहुंचाई जा रही है।

धारा 370 प्रभावहीन जम्मू कश्मीर विकास की मुख्य धारा में शामिल होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर देश में विशेष उत्साह व उल्लास का वातावरण है। हमारे जम्मू–कश्मीर के भाई बहनों को धारा 370 से आजादी मिली है। प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी को इसके लिए बधाई देते हुए कहा कि अब जम्मू–कश्मीर के लोग मुख्य धारा में शामिल होकर विकास की नई इबारत लिख सकेंगे। एक देश, एक विधान व एक निशान का संकल्प साकार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्काल तीन तलाक पर रोक के कानून से मुस्लिम महिलाओं को शोषण से आजादी मिली है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बडा कदम है। चंद्रयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छह सितम्बर का दिन ऐतिहासिक होगा, जब भारत का चंद्रयान चंद्रमा पर उतरेगा। हम सभी इसके साक्षी बनेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक छोटा पर्वतीय राज्य होने पर भी हम न केवल देश की इकोलोजी बल्कि देश की इकोनोमी में भी अहम् योगदान कर रहे हैं। हाल ही में सम्पन्न हिमालयन कॉन्क्लेव में 11 हिमालयी राज्यों द्वारा पर्यावरण व जैवविविधता के संरक्षण के साथ देश की समृद्धि में योगदान के लिए 'मसूरी संकल्प' पारित किया गया।

भ्रष्टाचार किसी भी रूप में बरदाश्त नहीं किया जाएगा

राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून लाने जा रही है। भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल और अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह अधिकारियों व कार्मिकों को चिन्हित कर अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति दी जाएगी। हमने सरकारी विभागों में आउटकम आधारित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सीएम डैशबोर्ड 'उत्कर्ष' बनाया है। आम जन को अपनी शिकायत या समस्या के निस्तारण के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए सीएम हेल्पलाईन 1905 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

प्रदेश में कनेक्टीवीटी का हुआ प्रसार

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से कनेक्टीवीटी पर काफी काम किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड़ व भारतमाला योजना पर तेजी से काम चल रहा है। देहरादून में डाट काली मंदिर के पास दो–लेन सुरंग, मोहकमपुर व अजबपुर और हरिद्वार में डौसनी में आर.ओ.बी. को निर्धारित समय अवधि से पूर्व ही बनाकर यातायात के लिए शुरू कर दिया गया है। टिहरी में डोबरा–चांटी मोटर झुला पुल का काम मार्च 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा।

महत्वाकांक्षी ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलमार्ग पर काम प्रारम्भ कर दिया गया है। देवबंद–रूड़की रेलमार्ग इस राज्य के विकास को एक नई गति प्रदान करेंगे। देहरादून–काठगोदाम के बीच नैनी–दून जन शताब्दी एक्सप्रेस की शुरूआत की जा चुकी है। राज्य में 13 हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार की पहल से देहरादून, पंतनगर व पिथौरागढ़ के लिए सस्ती हवाई सेवा प्रारम्भ कर दी गई है। देहरादून, देश के 23 शहरों से हवाई सेवा के माध्यम से जुड़ चुका है।

युवाओं को रोजगार सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए स्कूलों को स्मार्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी सरकारी विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। राजकीय इंटरकॉलेजों में 859 प्रवक्ताओं की भर्ती की गई है। राजकीय महाविद्यालयों में 877 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पिछले ढाई वर्ष में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग व उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा साढ़े पांच हजार से अधिक नई भर्तियां की गईं, जबकि लगभग पांच हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

देहरादून में देश की पांचवी साईंस सिटी, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, रानी पोखरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और पैठाणी में प्रदेश का पहला वोकेशनल कॉलेज बनने जा रहा है। डोईवाला में सीपेट शुरू किया जा चुका है। इसमें शत प्रतिशत प्लेसमेंट दिया जा रहा है। देश के पहले ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र एवं अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना यहां की गई है। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से अल्मोड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाईबर की स्थापना की जा रही है। युवाओं को प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने के लिए 'स्टार्ट अप पॉलिसी' लाई गई। वर्ष 2020 तक 200 स्टार्टअप शुरू किए जाने हैं इनमें से 157 स्टार्ट–अप मान्यता प्राप्त कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 11 हजार से अधिक उद्यमों की स्थापना हुई। इनमें लगभग 80 हजार लोगों को रोजगार मिला। इन्वेस्टर्स समिट के केवल 10 माह की अवधि में 16 हजार करोड़ रूपए से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है जिससे लगभग 40 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

स्वास्थ्य सूचकों में हुआ सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में डाक्टरों की तैनाती पर्वतीय क्षेत्रों में की है। वर्तमान में 2045 चिकित्सक तैनात किए गए हैं जबकि पूर्व में केवल 1081 थे। इसके अलावा 159 दंतचिकित्सकों की नियुक्ति भी की गई है। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को विस्तारित करते हुए अटल आयुष्मान योजना लागू की है। इसमें राज्य के समस्त परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपए तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। अभी तक 60 प्रतिशत परिवार कार्ड बनवा चुके हैं और 60 हजार से अधिक लाभार्थियों को निशुल्क उपचार की सुविधा दी जा चुकी है। राज्य में 169 हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य सूचकों में काफी सुधार हुआ है। संस्थागत प्रसव 50 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गए हैं। मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। उत्तराखण्ड में बालिका लिंगानुपात में सबसे अधिक सुधार हुआ है। प्रदेश में विगत दो वर्षों में बच्चों में टीकाकरण 87 प्रतिशत से बढ़कर 99 प्रतिशत हो गया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ग्रोथ सेंटर

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018–19 में 1,98,738 रूपए है जो कि देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से 72,332 रूपए अधिक है। विकास का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने व पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित एप्रोच पर ग्रोथ सेंटर विकसित किए जा रहे हैं। 58 ग्रोथ सेंटर को मंजूरी दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज के 5 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। गत वर्ष केदारनाथ में 2 करोड़ रूपए से अधिक का प्रसाद महिला समूहों द्वारा बेचा गया। प्रदेश के 625 मंदिरों में प्रसाद योजना का विस्तार किया जा रहा है। मंशादेवी, बदरीनाथ, जागेश्वर, बागेश्वर से शुरूआत हो चुकी है। आशा कार्यकत्रियों का वार्षिक पारिश्रमिक 5 हजार रूपए से बढ़ाकर 17 हजार रूपए किया है। 'मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना' में बीस हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के ढ़ाई लाख बच्चों को निःशुल्क दूध उपलब्ध कराया जा रहा है।

खेती में 'मिट्टी से बाजार तक' की रणनीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 'मिट्टी से बाजार तक' की रणनीति पर काम किया जा रहा है। भारत सरकार के सहयोग से 3340 करोड़ की समेकित सहकारी विकास परियोजना प्रारम्भ की गई है। इससे लगभग 55 हजार लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। परम्परागत कृषि विकास योजना के पहले चरण में स्वीकृत 3900 जैविक क्लस्टरों में काम शुरू किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उत्तराखण्ड में लगभग 85 प्रतिशत लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। 5 लाख 50 हजार किसान लाभान्वित भी हो चुके हैं। प्रदेश में लघु, सीमांत व बी.पी.एल. किसानों को 1 लाख रूपए व स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपए तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिन किसान भाईयों के पास कृषि उपकरण नहीं हैं, उनके लिए ''फार्म मशीनरी बैंक'' योजना शुरू की गई है। इसके लिए राज्य सरकार 80 फीसदी तक सब्सिडी उपलब्ध करा रही है।

क्लीन एनर्जी पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि घर–घर तक बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना के तहत शत प्रतिशत विद्युतिकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। उत्तर भारत के सभी राज्यों में उत्तराखण्ड में लगभग सभी श्रेणियों में सबसे कम दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

'क्लीन–एनर्जी' पर विशेष फोकस किया जा रहा है। पाईननिडिल व अन्य बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन नीति लागू की गई है। इसके तहत अभी तक 21 योजनाएं आवंटित की जा चुकी है। इसमें जंगलों से पिरूल कलेक्शन के लिए महिला समूहोंको 1 रूपया प्रति किलो दर से भुगतान मिलेगा। प्रदेश में ऐसे 6 हजार पिरूल संयंत्र स्थापित करने की योजना है। इससे लगभग 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

संशोधित सौर ऊर्जा नीति 2018 में 5 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजना, पर्वतीय क्षेत्रों के स्थाई निवासियों के माध्यम से स्थापित की जा सकती हैं। अभी तक 208 लोगों को 148 मेगावाट की परियोजनाओं के आवंटनपत्र सौंपे जा चुके हैं।

जनसहयोग से जलसंरक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल शक्ति अभियान में केंद्र सरकार के सहयोग से 'हर घर जल' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। प्रदेश की जलनीति तैयार की जा रही है। देहरादून में सूर्यधार, पिथौरागढ़ में थरकोट, चम्पावत में कोलीढ़ेक व अल्मोड़ा में गगास पर जलाशय का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। कोसी, बिंदाल व रिस्पना के पुनर्जीविकरण के लिए जन सहभागिता से व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

ग्रेविटी आधारित सौंगबांध बनने से देहरादून को 30 वर्ष तक जल की अबाध पूर्ति होगी। वर्ष 2022 तक 5 हजार समस्या ग्रस्त प्राकृतिक जलस्त्रोतों को पुनर्जीवित व सवंर्धित करने का लक्ष्य रखा गया है। मां गंगा का उद्भव स्थल होने के नाते नमामि गंगे अभियानमें उत्तराखण्ड की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके तहत उत्तराखण्ड में स्वीकृत 21 परियोजनाओं में से 9 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं जबकि शेष योजनाएं फरवरी 2020 तक पूरी कर ली जाएंगी।

होम–स्टे व एडवेंचर टूरिज्म से गांव–गांव पहुंच रहा पर्यटन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण करते हुए इसे पहले से भी अधिक भव्यता प्रदान की गई है। बद्रीनाथ धाम के लिए भी कार्ययोजना बनाई जा रही है। इस बार चारधाम व हेमकुण्ड साहिब के दर्शनों के लिए रिकार्ड संख्या में श्रद्धालु आए हैं।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। 'होम–स्टे' के माध्यम से पर्यटन अब ग्रामीणों की आजीविका का साधन बन रहा है। 13 जिलों में 13 नए थीम बेस्ड डेस्टीनेशन विकसित कर रहे हैं। उत्तराखण्ड में माउंटेनियरिंग, रिवरराफ्टिंग, ट्रैकिंग, केम्पिंग, पैराग्लाईडिंग, माउंटेन बाईकिंग आदि की बहुत सम्भावनाएं हैं। इसके लिए साहसिक पर्यटन का अलग से निदेशालय बनाया जा रहा है। वैलनेस टूरिज्म पर भी फोकस किया जा रहा है।

टिहरी झील में सी–प्लेन के संचालन के लिए एमओय ूकिया गया है। पिथौरागढ़ में देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनाने जा रहे हैं। देहरादून–मसूरी रोपवे परियोजना का शिलान्यास किया जा चुका है। सुरकंडा देवी व पूर्णागिरी देवी मंदिर के लिए रोपवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में फिल्मों की अधिक से अधिक शूटिंग हो, इसके लिए हमने राज्य में फिल्मों के अनुकूल माहौल बनाया है। यही कारण है कि भारत सरकार द्वारा 'मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग' भी घोषित किया गया है।

इनकम इंडेक्स के साथ हैप्पीनेस इंडेक्स भी महत्वपूर्ण

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने व हर उत्तराखण्डी के जीवन में खुशहाली लाने का हर सम्भव प्रयास कर रही है। कोशिश है कि इनकम इंडेक्स के साथ हैप्पीनेस इंडेक्स में उत्तराखण्ड आगे रहे। एक भारत–श्रेष्ठ भारत के लिए सभी को आगे आना होगा।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।